

पहल • केंद्रीय कौशल विकास मिशन के अपर सचिव व सलाहकार ने किया स्किल सेंटर का भ्रमण

कौशल व हुजर के लिए चलेगी संकल्प योजना

• 27 व 28 फरवरी को होनेवाली संकल्प कार्यशाला की समीक्षा की गयी

विशेष संवाददाता P रावती

केंद्रीय कौशल विकास मिशन के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा आरंभ की गयी संकल्प योजना अब झारखंड में भी चलनेगी। आजीविका संवर्धन के लिए कौशल व हुजर की जागरूकता को ही संकल्प नाम दिया गया है। कौशल विकास की इस महत्वपूर्ण योजना के लिए वितीय प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। संकल्प कार्यक्रम कौशल विकास का एक विशिष्ट समेकित स्वरूप होगा, जिसमें केंद्रीकृत स्वरूप में कौशल विकास के सभी कार्यक्रमों को समाहित



स्किल सेंटर का भ्रमण करते हुए अपर सचिव व अन्य अधिकारी.

किया जाएगा. यह योजना देश के राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी संपूर्ण इकोसिस्टम, कौशल विकास (एनएसडीए) तथा राष्ट्रीय कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), विकास निगम (एनएसडीसी),

राज्य सरकार के कौशल विकास के सश्री स्टैक होल्डर को कवर करेगी. संकल्प कार्यक्रम के तहत महिलाओं एवं वींचित समूहों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहुंच सुनिश्चित किया जाएगा. इस कार्यक्रम के परिणामों को राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा विश्व बैंक के द्वारा मानक सूचकांक निर्धारित कर आकलन किया जाएगा. झारखंड में संकल्प कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राजधानी में 27 व 28 फरवरी 2019 को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, दिल्ली, तेलंगाना आदि जगहों के कौशल विकास स्टैकहोल्डर भाग लेंगे. कार्यशाला की तैयारियों की समीक्षा एवं झारखंड स्किल इकोसिस्टम से अगला होने के उद्देश्य से केंद्रीय कौशल विकास व व उद्यमिता मंत्रालय की अपर सचिव जुबिका पटनाकर तथा कौशल विकास की सलाहकार अक्नोत कोर ने झारखंड का दो दिनों तक दौर किया. मंगलवार को सभी अधिकारी कौशल विकास मिशन के निदेशक रवि रंजन व सीडओ अमर झा व अन्य अधिकारियों के साथ सीएमसी मिटकान भाग स्किल सेंटर, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र कटहल मोड़ का दौर किया. बुधवार को सभी अधिकारी टाटीसिलव स्थित दो स्किल सेंटर गये, जहां उन्होंने प्रशिक्षण केंद्रों के प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण कक्ष व प्रायोगिक सामग्रियों की देखा और संतुष्ट हुए. केंद्रीय अधिकारियों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से बात भी की.

हिन्दुस्तान

दिनांक:- 07.02.2019

पृ.- 02

राज्य में शुरू होगा 'संकल्प' 27 और 28 को कार्यशाला

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

केंद्र की तर्ज पर झारखंड में भी संकल्प (आजीविका संवर्धन के लिए कौशल व हुनर की जागरूकता) योजना लागू होगी। इसमें कौशल विकास के चल रहे सभी कार्यक्रम समाहित हो जायेंगे। विश्व बैंक द्वारा इसे वित्तीय सहयोग भी दिया जायेगा। झारखंड में इसकी शुरुआत करने के लिए 27-28 फरवरी को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

संकल्प में सभी इकोसिस्टम, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और सरकार के कौशल विकास के सभी स्टैक होल्डर को समाहित किया जायेगा। संकल्प को शुरू करने का उद्देश्य उच्च गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना तैयार करने, संचालन व मॉनिटरिंग और क्षमता विकास है। राज्यस्तरीय कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश, मेघालय, दिल्ली व तेलंगाना के कौशल विकास स्टैकहोल्डर भाग लेंगे। इसको लेकर कौशल विकास मंत्रालय की अपर सचिव जुथिका पटनाकर व सलाहकार अपनीत कौर ने झारखंड का दौरा किया।

Centre's Sankalp programme to be launched in State



Team of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) in Ranchi to review the preparations for launch of Sankalp scheme in Jharkhand Pioneer photo

PNS ■ RANCHI

The Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP) programme of Union Government will soon be implemented at Jharkhand. The scheme is being launched with the aim to preparing and implementing high quality training modules and will be aided by World Bank.

The programme was launched at centre on July 15, 2018 under National Skill Development Mission by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE).

A state level workshop for the implementation of the programme will be organized in Ranchi on February 27 and 28 in which stakeholders from not just Jharkhand but other states including Himachal Pradesh, Meghalaya, Delhi and Telangana would participate.

Juthika Patnagar, additional secretary, MSDE was in Ranchi on Tuesday and Wednesday to review the preparations for the workshop. Meanwhile, in another

instance, secretary, higher, technical education and skill development department Rajesh Sharma held a meeting with industrial units, public sector units and educational institutions to discuss the operation of engineering colleges and polytechnic colleges of the state on public private partnership (PPP) mode.

Tata Steel Ltd., Jindal Steel Pvt.Ltd., CCL, Orion Edutech, OP Indal, Centurian University, Centum Learning, Team Lease, Centurion University where some of the major participating institutions.

The representatives were informed that the operations of technical institutions would be given up to 25 years and the companies can run the institutions using their CSR funds.

The 12 newly constructed technical institutions which have to be run on PPP mode include four engineering colleges, one each at Ramgarh, Jamshedpur, Koderma and Palamu and eight polytechnic colleges at giridih, Godda, Lohardaga, Hazaribag, Chatra, Khunti, Jamtara and Palamu.